

बीमाकृत मजदूर बीके अस्पताल में तथा आम नागरिक ईएसआई अस्पताल में इलाज के नाम पर धक्के खा सकेंगे

खट्टर सरकार का षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे मजदूर संगठन

फरीदाबाद (म.मो.) राज्य की जनता को स्वास्थ्य सेवायें देने में पूरी तरह विफल खट्टर सरकार की गिर्द दृष्टि आज कल ईएसआई कार्पोरेशन के अस्पतालों पर पड़ी हुई है। यह ठीक ऐसा ही है जैसे कि अपना घर तो संवारना नहीं दूसरे के संवरे हुए घर में घुस जाना। इस विषय पर 'मजदूर मोर्चा' के गतांक में पूरी जानकारी काफ़ी विस्तार से दी गई है।

संदर्भवश सुधी पाठक समझ लें कि एनएच तीन स्थित ईएसआई अस्पताल व बीके अस्पताल की सेवाओं में ऐसा क्या अंतर है कि जिसके लिये खट्टर महाशय ईएसआई अस्पताल में सेंध लगाना चाहते हैं। दरअसल बीके अस्पताल में चिकित्सा सेवायें देने का कोई माहौल ही नहीं है। यहां का लगभग सारा स्टाफ़ शातिर शिकारी की भाँति हर समय शिकार की टोह में रहता है। कैजुल्टी में आये लड़ाई-झगड़ों के मामलों में इश्वत लेकर कुछ का कुछ लिख दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने तक में अच्छी-खासी वसूली की जाती है। तरह-तरह के प्रमाणपत्र देने का धंधा भी अच्छी कमाई का साधन है। जिले भर के प्राइवेट अस्पतालों पर छापे मारने व उनकी नकेल कसना भी यहां के डॉक्टरों की कमाई का बड़ा साधन है।

इलाज के नाम पर आने वाले गरीब मजदूरों को वांछित सेवायें देने की अपेक्षा उन्हें कमीशनखोरी के चक्रकर में इधर-उधर भटकाया जाता है। इनकी लैबोरेटी में अव्वल तो टैस्ट होते ही नहीं और जो हो भी जाये तो वे भरोसेमंद नहीं होते। मरीज़ को देखने वाले डॉक्टर ही चुपचाप मरीज़ को इशारा कर देते हैं कि बाहर से टैस्ट करा लाओ। इसी तरह एक्सरे व अल्ट्रासाउंड का काम भी बाहर बैठे



मुख्यमंत्री

दुकानदारों से ही कराया जाता है। वहां से शाम तक कमीशन सम्बन्धित डॉक्टरों को पहुंच जाता है।

'मजदूर मोर्चा' ने पिछले दो अंकों में कमीशनखोरी का एक बेहतरीन उदाहरण प्रकाशित किया था। उसमें बताया गया था कि कैसे स्थानीय आठ सेक्टर की घरों में काम करनी वाली एक गरीब महिला 9 मई को प्रातः चार बजे अपनी डिलिवरी कराने हेतु बीके अस्पताल आई थी। वहां इयूटी डॉक्टर मंजरी के अनुपस्थित होने के चलते पूजा नामक एक नर्स ने उस महिला को बताया कि बच्चे की जान खतरे में है इसलिये तुरंत सेक्टर आठ स्थित गोयल नर्सिंग होम चली जाओ। नर्स ने वहां फ़ोन भी कर दिया। महिला जब वहां पहुंची तो उन्होंने 40 हजार रुपये मांगे। इतना रकम न होने के चलते वे लोग मुकेश कॉलोनी बल्लबगढ़ के एक छोटे से क्लीनिक जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही महिला की स्वतः ही साधारण डिलिवरी हो गई जिसके लिये उन्हें 11 हजार रुपये देने पड़े।

खट्टर अपने इन अस्पतालों की नकेल कसने की बजाय सही ढंग से काम करने वाले ईएसआई अस्पतालों में सेंध मारना चाहते हैं। ईएसआई के एनएच-3 अस्पताल में हर महीने करीब 130 साधारण डिलिवरी तथा 100 के करीब सींजेरियन डिलिवरियां होती हैं। बीते चार सालों के उपलब्ध अंकड़ों के अनुसार एक भी केस कहीं रेफर नहीं किया गया। स्त्रीरोग की ओपीडी में करीब पांच हजार महिलायें प्रति माह आती हैं, उन्हें भी कहीं रेफर नहीं किया जाता। इस अस्पताल में 24 घंटे महिला रोग सम्बन्धी एवं प्रसूति विभाग चलता रहता है और हर शिफ्ट में पूरा स्टाफ़ किसी भी प्रकार के ऑपरेशन आदि के लिये तैयार रहता है।

इसके अलावा ईएसआई अस्पताल से कभी किसी मरीज़ ने किसी स्टाफ़ के विरुद्ध पैसे मांगने की कोई शिकायत नहीं की, जबकि बीके अस्पताल में सफाई कर्मचारी से लेकर डॉक्टर तक तमाम कर्मचारी आगान्तुक मरीज़ को किसी न किसी बहाने लूटने की ताक में रहते हैं। ईएसआई अस्पताल में हर समय मरीज़ों की शिकायत सुनने के लिये चिकित्सा अधिक्षक एवं डीन उपलब्ध रहते हैं। वे लोग न केवल शिकायत सुनते ही हैं, तुरन्त एक्शन भी लेते हैं जिसके चलते मरीज़ों की शिकायत नाम मात्र की होती हैं। इसके विपरीत खट्टर के सरकारी अस्पतालों में न कोई सुनने वाला है न कोई किसी को पूछने वाला है क्योंकि नीचे से ऊपर तक हमाम में सभी नंगे हैं। हां, यदा-कदा ड्रमेबाजी के लिये राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अस्पतालों पर छापेमारी का खेल जरूर खेलते रहते हैं। ऐसे में भला कौन बीमाकृत श्रमिक ईएसआई अस्पताल छोड़कर खट्टर के अस्पतालों में मरने को जाना चाहेगा?

पीएमओ सविता यादव एक भी मरीज़ नहीं देखती



डॉक्टर सविता यादव बेहतरीन स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के साथ-साथ बहुत अच्छी सर्जन भी हैं। इन्होंने सर्जरी में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। बीते तीन साल से यानी जब से वे इस अस्पताल की प्रिंसिपल मेंडिकल ऑफ़िसर बनी हैं, तब से इन्होंने एक मरीज़ नहीं देखे। और तो और अस्पताल से सम्बन्धित कोई शिकायत तक भी यह सुनना पसंद नहीं करती।

माना कि इस पद पर प्रशासनिक जिम्मेवालाया भा काफ़ा हाता है इसालय मरीज़ देखने की फुर्सत कम ही मिल पाती है। लेकिन सेवा नियमों के अनुसार इन्हें समय निकाल कर मरीज़ों को जरूर देखना चाहिये। यही नियम तमाम उन डॉक्टरों पर भी लागू होता है जो प्रशासनिक पदों पर यानी सिविल सर्जन अथवा डिप्टी सिविल सर्जन आदि पदों पर तैनात हैं। सिविल सर्जन विनय गुप्ता प्रशासनिक कार्यों में बेशक निल बटा सनाटा हैं लेकिन हर शनिवार को वे नियमित रूप से ओपीडी में बैठकर मरीज़ों को देखते हैं। अच्छी बात है, कि वे मरीज़ देखते हैं, लेकिन वे एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते उन तमाम डॉक्टरों को मरीज़ देखने के लिये आदेश क्यों नहीं देते जो दफ्तरी बाबू बनकर रह गये हैं? सिविल सर्जन अथवा पीएमओ द्वारा मरीज़ों को देखा जाना कोई अजूबा नहीं है। इन पदों पर रह चुके दर्जनों डॉक्टर मरीज़ देखा करते थे।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।

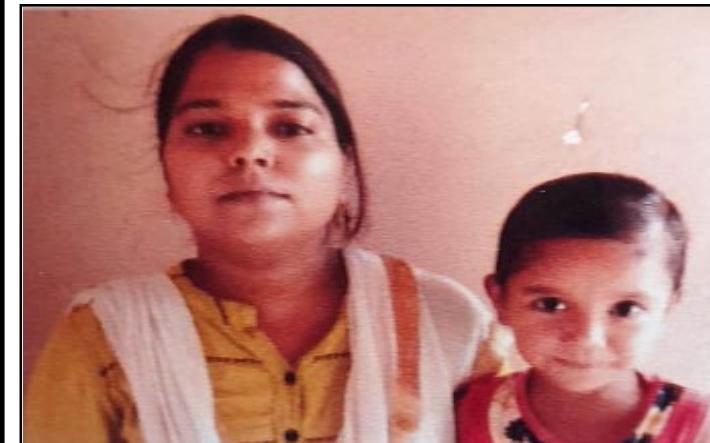
बस रैफरल ही रैफरल!

आरटीआई द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 3 वर्षों में 1511 प्रसूति केस रेफर किये गये। 2019 में 665 केस, 2020 में 481 केस, 2021 में 348 केस तथा जनवरी 2022 तक 17 केस रेफर किए हैं। इसके अलावा बाल रोग विभाग से 2019 में 43 केस, 2020 में 15 केस, 2021 में 46 केस तथा जनवरी 2022 तक 03 केस रेफर किये गये। आईपीडी विभाग से 2019 में 227 केस, 2020 में 180 केस, 2021 में 144 केस तथा जनवरी 2022 तक 09 केस रेफर किये गये। विशेष नवजात बच्चा वार्ड से 2019 में 264 केस, 2020 में 223 केस, 2021 में 136 केस तथा जनवरी 2022 तक 13 केस रेफर किये।



महिलाओं को संस्थानात प्रसूति सुविधायें उपलब्ध कराने का फ़िटोरा पीटने वाली सरकार ने कभी नहीं देखा कि उसके द्वारा 'स्थापित' कराई गई तमाम सुविधाओं की वास्तविकता क्या है? जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज राज्य भर के अस्पतालों में छापेमारी का नाटक करते घूमते रहते हैं, यदि उनकी नीयत काम करने की हो तो अपने कार्यालय में बैठे बैठे ही राज्य भर के अस्पतालों आदि की स्थिति को जान सकते हैं। राज्य भर के अन्य अस्पतालों का तो पता नहीं परन्तु बीके अस्पताल में तैनात स्टाफ़ ने रेफर करने को लूट कराई था अच्छा-खासा धंधा बना लिया है। बेशक काग़ज पर तो मरीज़ दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को ही रैफर किये जाते हैं, परन्तु उन्हें भयभीत करके कान में किसी स्थानीय नर्सिंग होम का पता बता दिया जाता है। इसके अलावा बीके अस्पताल के सभी विभागों के मिलाकर बीते तीन वर्षों में 2772 मरीज़ों को रैफर किया गया है।

रेफर करने का धंधा बहुत पुराना है



गढ़खेड़ा गांव की रजनी नामक महिला अक्टूबर 2015 को बीके अस्पताल में डिलिवरी हेतु रात के करीब 12 बजे पहुंची थी जिसे इयूटी डॉक्टर की अनुपस्थिति में नर्स द्वारा दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल को रेफर कर दिया गया था। रेफर करते वक्त उस महिला की परिजनों को अति गंभीर स्थिति बता कर बुरी तरह से भयभीत कर दिया गया था। डर के मारे परिजन तुरन्त उसे लेकर सफदरजंग अस्पताल पहुंच गये। वहां फ़र्श पर पड़ी मरीज़ों की दुदेशा देखकर, कराही हुई रजनी को बापस सेक्टर 11 फरीदाबाद के अश्वनी नर्सिंग होम में ले आये। यहां आते ही उसकी साधारण डिलिवरी हो गई।

इतना ही नहीं उक्त महिला शुरू से ही नियमित रूप से अपने गांवों के निकट दिलालपुर में स्थित हेल्थ सेन्टर से चेकप करती रहती थी। लेकिन डिलिवरी वाले दिन जब शाम को आठ बजे वह वहां पहुंची तो स्टाफ़ नदारद था। केवल एक नर्स मौजूद थी जिसने उसे बल्लबगढ़ तथा बल्लबगढ़ वालों ने उसे बीके रेफर कर दिया था। सारा मामला 'मजदूर मोर्चा' में प्रकाशित किया गया था। इसके जवाब में तत्कालीन सीएमओ गुलशन अरोड़ा ने मामले की जांच का आदेश दिया था। उस जांच का अभी तक कोई अता-पता नहीं। यदि तत्कालीन सीएमओ ने इस मामले का कड़ा संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की होती तो इस धंधे पर रोक लग सकती थी।